

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश सहारण, आर.ए.एस.

प्र.सं. 90/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/32

1. सुखविन्द्र सिंह सिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ (विलोपित)
2. तहसीलदार अनूपगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. दौलत सिंह (मृतक)—वारिसान
 - 1.1 बलराज सिंह पुत्र दौलतसिंह
 - 1.2 सुजाता पुत्री दौलत सिंह
 - 1.3 ममता उर्फ माधवी पुत्री दौलत सिंह
 - 1.4 वनीता सिंह पुत्री दौलत सिंह
2. रमेश कुमार पुत्र मनोहर सिंह जाति यादव सा. गांधी नगर, बीकानेर।
3. सुरेन्द्र कुमार(मृतक)—वारिसान
 - 3.1 कमला पत्नी स्व. सुरेन्द्र कुमार
 - 3.2 विषयंत पुत्र सुरेन्द्र कुमार
 - 3.3 अंशु पुत्री सुरेन्द्र कुमार
 - 3.4 अर्चना पुत्री सुरेन्द्र कुमार

जाति यादव निवासीगण
वार्ड नं. 12 पुलिस थाने के
पीछे, अनूपगढ़

जाति यादव निवासीगण हाल
जी-90 समता नगर, बीकानेर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22(3) राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975

उपस्थिति :-

1. तहसीलदार अनूपगढ़ — प्रार्थी
2. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1.1 से 1.4(जरिए मु.आ. अप्रार्थी सं. 1.1)
3. स्वयं, अप्रार्थी सं. 3.1 से 3.4(जरिए मु.आ. अप्रार्थी सं. 3.2)

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 05.09.24

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. प्रार्थी सुखविन्द्र सिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 22(3) आई.जी.एन.पी आवंटन के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ के चक 16 ए के मु.नं. 299/447 का किला नं. 1 ता 21 की कुल 14 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि जरिये मि.स. 20/80 विशेष आवंटन निर्णय दिनांक 24.09.1980 व 06.03.1981 को विशेष आवंटन दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनोहर सिंह एवं मु.न. 299/447 का कुल 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि जरिये मि.स. 68/81 दिनांक 06.03.1981 विशेष आवंटन रमेश कुमार द्वारा करवा ली। आवंटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार का देहान्त हो चुका है। दौलत सिंह सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार पुत्रान मनोहर ने अपने अपने आवेदन पत्र में कथन किया कि वह आवंटन नियमों के खंड 05, 13 व 17 के तहत परिभाषिक व्यक्ति है तथा इन खंडों के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

तहत यह भूमि आवंटन करवाने के पात्र हैं, जबकि दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार पुत्रान मनोहर सिंह अपने-अपने प्रार्थना पत्र के साथ उपनिवेशन तहसीलदार राजस्थान नहर योजना विजयनगर के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचकर भूमिहीन काश्तकार के प्रमाण पत्र तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार से मिथ्या बनवाकर पेश किए हैं जिस पर दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार ने तत्कालीन आवंटन अधिकारी से सातगांठ की जिसपर आवंटन अधिकारी ने दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार पुत्रान मनोहर सिंह को खंड 5, 13 व 17 के अनुसार इनके भूमिहीन प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र मानकर उक्त भूमि आवंटित की एवं दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार पुत्रान मनोहर सिंह भूमिहीन काश्तकार नहीं थे जबकि रमेश कुमार पुत्र मनोहर सिंह जो सद्भाविक कृषि पेशा व भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति भी नहीं था क्योंकि वह एमबीबीएस डिग्रीधारक डॉक्टर है दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार ने तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार से मिलकर भूमिहीन प्रमाण पत्र मिथ्या तैयार करवाया है जबकि आवंटन नियम 2 के खंड 13 के अनुसार ऐसे व्यक्ति का सद्भाविक कृषक या कृषक श्रमिक होना जरूरी था ऐसे व्यक्ति का 25 बीघा से कम भूमि धारित करने वाला होना चाहिए जबकि इस प्रमाण पत्र में व इस पर अंकित हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रमेश कुमार के पास 32 बीघा 1 बीरवा भूमि कमांड भूमि स्वयं रमेश कुमार के पास थी इसके अलावा वह पेशे से डॉक्टर था तथा दौलत सिंह के पास 28 बीघा स्वयं की व सुरेन्द्र कुमार के पास 33.14 बीघा भूमि स्वयं की थी ऐसी स्थिति में उक्त तीनों ही व्यक्ति भूमिहीन नहीं होते हुए तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार ने आपराधिक षडयंत्र रचकर भूमिहीन प्रमाण पत्र मिथ्या व कूट रचित तैयार किया जबकि तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार ने यह जानते हुए भी कि वे दरस्तावेज मिथ्या हैं उसके बावजूद हस्ताक्षरित कर जारी किया एवं दौलत सिंह सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार उक्त भूमि को आवंटन कराने का पात्र नहीं होते हुए जिन्होंने नगरपालिका अनूपगढ़ के सीमा क्षेत्र के विपत्ती हुए बहुमूल्य भूमि का हथियाने के लिए तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार से आपराधिक षडयंत्र रचकर भूमिहीन का मिथ्या प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदन पत्र में मिथ्या कथन कर व आवेदक पत्र में भूमिहीन होने का झूठा शपथ पत्र पेश कर आवंटन अधिकारी से सातगांठ कर उक्त भूमि अपने नाम से विधि विरुद्ध आवंटन करवाकर राज्य सरकार की भूमि प्राप्त कर राज्य सरकार को करोड़ों रूपए का नुकसान पहुंचाया है एवं अप्रार्थीगण सुरेन्द्र कुमार दौलत सिंह, रमेश कुमार तीनों ही भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते ना ही उनका पेशा काश्तकारी था बल्कि अनूपगढ़ व बीकानेर शहर में रहकर दुकानदारी करते थे। नियम 22(3) विधि के विरुद्ध आवंटन किए गए को खारिज करवाने का प्रावधान है तीनों ही आवंटन के पात्र नहीं थे। इसलिए अप्रार्थीगण ने आवंटन अधिकारी को धोखे में रखकर भूमि आवंटन करवाई है जो काबिले खारिज है एवं उपखंड अधिकारी के भी रिपोर्ट करवाई थी उनके द्वारा जांच करके 01.02.2018 को आवंटन को विधि विरुद्ध मानते हुए अदालतवाला में रिपोर्ट पेश कर दी थी एवं उक्त भूमि काबिल कृषि थी इसमें बिना भूरूपांतरण करके करवाए फैक्ट्रियां व धर्मकांटा लगा लिया है जो नियमों के स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए उक्त रकबे को खारिज किया जाना इंसाफ की दृष्टि से आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसील अनूपगढ़ के चक 16ए मु.न. 6 प.स. 299/447 की कुल 3.858 हैक्. भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाने के लिए निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1.1 से 1.4 जरिए मु.आ. अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं. 3.1 से 3.4 जरिए मु.आ. अप्रार्थी सं. 3.2 के उपस्थित हुए।

अतिरिक्त निवेदन
अनूपगढ़

अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आवंटित भूमि विक्रय की जा चुकी है। तथा वर्तमान रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 1 व 3 के वारिसान के नाम से दर्ज है जिसकी पुष्टि तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1.1 से 1.4 व 3.1 से 3.4 ही प्रकरण से हितबद्ध पक्षकार हैं जो कि उपस्थित हो चुके हैं। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात पेश किये गये। क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण पत्रावली पहले जिला कलक्टर न्यायालय अनूपगढ़ तत्पश्चात जिला कलक्टर महो. अनूपगढ़ के आदेशों की पालना में हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज की जाकर उभयपक्ष को तलब किया गया। इस दौरान दिनांक 12.12.2023 को तहसीलदार अनूपगढ़ को बतौर प्रार्थी पक्षकार प्रतिस्थापित किया गया तथा दिनांक 12.10.2023 को प्रार्थी सतनाम सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र विज्ञो हेतु निवेदन किये जाने के आधार पर प्रार्थी सतनाम सिंह की हद तक प्रकरण की कार्यवाही शेष करते हुए प्रार्थी सतनाम सिंह का नाम हटाते हुए शीर्षक में प्रार्थी के नाम के आगे विलोपित अंकित करने के आदेश पारित किये गये।

3. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कृषि भूमि दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनोहर सिंह को आवंटित होने के तथ्य रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है तथ्य रिकॉर्ड अनुसार दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार का देहान्त होना स्वीकार है। दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार हम अप्रार्थीगण के पति/पिता आवंटन नियम उपनियम के तहत ही कृषि भूमि का आवंटन करवाया गया जो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं था। पात्रता के आधार पर आवंटन किया गया जो सही आवंटन है। उपरोक्त भूमि वर्ष 1980-81 में विशेष आवंटन के तहत आवंटित की गई थी। प्रार्थी परिवार की आर्थिक स्थिति एवं स्टेटस वर्तमान स्टेटस से भिन्न था। चूंकि आवंटन करवाने वाला व्यक्ति 20 वर्ष से राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक शर्त थी। विशेष आवंटन के नियम 2 के खंड 5, 13 व 17 के तहत पात्रता रखते थे व विशेष आवंटन का पात्र मानते हुए ही आवंटन अधिकारी द्वारा विशेष आवंटन किया गया था। जिसमें कोई भी गलत प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। तत्कालीन परिस्थितियों के तहत एवं पात्रता के आधार पर आवंटन किया गया था जो सही एवं उचित था। विशेष आवंटन की समस्त शर्तों के तहत आवंटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार को आवंटित किया गया था। जिसमें नियम 2 के तहत खंड 13 के प्रावधान लागू नहीं होते। तथाकथित प्रार्थी ने इस मद में जो उक्त नियमों को परिभाषित किया गया है व हस्तगत प्रकरण पर चर्चा नहीं होते और न ही किसी प्रकार से किसी तथ्यों को छुपाया गया है तथा ना ही प्रसंगत भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित थी और विशेष आवंटन में ही नियमानुसार आवंटन किया गया है। मूल आवंटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार 20 वर्षों से राजस्थान के मूल निवासी होने के कारण विशेष आवंटन करवाने के पात्र थे तथा विशेष आवंटन नियमों के तहत ही सक्षम अधिकारी द्वारा समस्त जांच कर आवंटन किया गया था। जिसके खातेदारी अधिकार भी मूल आवंटियों के नाम प्रदत्त की गई एवं 40 वर्षों के उपरांत आवंटन आदेश को चुनौति दी गई जो विधि विपरीत है। प्रार्थी ने अधिकाररहित झुली शिकायत प्रस्तुत की है। अप्रार्थी संख्या 02 लिखित बहस प्रस्तुत की उपरोक्त दोनों प्रकरण आवंटन को रद्द करने के शिकायत प्रार्थना पत्र है। सुविधा की दृष्टि से दोनों में ही बलराज सिंह पक्षकार मुकदमा है। प्रार्थी सतनाम सिंह द्वारा उक्त दोनों शिकायतें प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 7 के प्रकाश में एवं दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार सद्भाविक कृषक ना होने के आधार पर शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया है। शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है। इसी कृषि भूमि के संबंध में श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के एक प्रकरण धारा 21 राजस्थान उपनिवेश अधिनियम के तहत पेश किया हुआ है। ऐसी स्थिति में हस्तगत दोनों प्रार्थना

पत्र निरस्त किए जान योग्य है। मूल आवंटी द्वारा कोई मिथ्या घोषण नहीं की गई एवं ना ही कोई तथ्य छुपाया गया है, वर्ष 1980-81 में विशेष आवंटन के तहत जो जमीन आवंटित की गई वो पात्रता के आधार पर एवं आवंटन नियमों के तहत ही विशेष आवंटन के पात्र मानते हुए ही आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर नियम 11.14 लागू नहीं होते एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी सतनाम सिंह द्वारा व्यक्तिगत रजिस्ट्रार के कारण यह शिकायत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि में आवंटन के बाद से ही कब्जा चला आ रहा है व खातोदारी अधिकारी भी प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी स्थिति में आवंटन निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। तहसीलदार अपनी बहस में कथन किया कि दौलत सिंह पुत्र मनोहरसिंह के वारिसान बलराजसिंह व युवराजसिंह जाति यादव एवं सुरेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह के वारिसान कमला यादव, विशयंतसिंह एव अन्य के नाम कुल 9 खातों में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर दौलत सिंह-सुरेन्द्रसिंह पि. मनोहर सिंह जाति यादव ई.स. 07 दिनांक 20.19.1989 से पटवार रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि आदिनाक तक उक्त रकबे में इनके जायज वारिसान बलराजसिंह व युवराज सिंह पि. दौलतसिंह, कमला यादव, विशयंतसिंह व अन्य पि. सुरेन्द्रसिंह के कब्जा में व देखरेख में है। आवंटियों का कब्जा जसिये वारिसान इन्तकाल है एवं आवंटियों के वारिस अनूपगढ़ के निवासी है।

5. प्रार्थी सुखविन्द्रसिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 पुरान अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 12.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का मध्य प्लॉट का विवाद चल रहा था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 22(3) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पेश किया जिसके चलते प्रार्थी उक्त प्रकरण में पेश किया गया था जिसमें अब प्रार्थी का अप्रार्थीगण से पंच पंचायत की समझाइश से एवं लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा हो गया है। जिससे हम पक्षकारन सहमत हैं। अब प्रार्थी उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। मुकदमा चलने से आपसी मुकदमा विवाद बड़ेगा जिससे समय व धन की भी बर्बादी होना इसलिए सद्भाविक रूप से पक्षकारन के बीच में आपस में राजीनामा हो गया।

6. पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार अनूपगढ़ व अप्रार्थीगण वकील की बहस एवं प्रार्थी सुखविन्द्रसिंह के प्रार्थना पत्र पर गहनता से मनन किया गया। दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार का पेशा कृषि था एवं अप्रार्थीगण 1 के अधिवक्ता के तहत सद्भाविक कृषक वह व्यक्ति है जिसकी प्राथमिक स्रोत कृषि है चूंकि आवंटी ने अपने विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र में स्वयं द्वारा धारित एवं पिता की भूमि में अपना हिस्सा वर्णित किया है जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि आवंटी सद्भाविक कृषक थे जो कृषि भूमि काशत व कृषि कार्य करते थे और जिनकी आय का स्रोत कृषि था (राजस्थान उपनिवेशन इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13ए विशेष आवंटन द्वारा विक्रय नियम में सद्भाविक कृषक दिनांक 15.07.1993 को संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और यह नियम तुरंत प्रभाव में आना प्रभावित किया गया सुरेन्द्र सिंह नगरपालिका चैयरमैन बनने एवं रमेश कुमार के पास एमबीबीएस डिग्री के होने के आधार पर आवंटन निरस्त करना कतई न्यायसंगत विधिक संगत नहीं है। नगरपालिका का चैयरमैन एवं एमबीबीएस डिग्री कोई व्यवसाय या आय स्रोत नहीं है धारित भूमि एवं विशेष आवंटन द्वारा आवंटित भूमि मिलाकर भी आवंटी सीलिंग सीमा से कम भूमि धारित करते हैं आवंटी राजस्थान के मूल निवासी एवं सद्भावी कृषि कार्य से आजीविका निर्वाह करते थे जिसकी पृष्टि उपलब्ध

रिपोर्ट व दस्तावेजों से हो चुकी है पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि आंवटी की आय का स्रोत कृषि नहीं था।

7. भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित होने की गलत व निराधार है राजस्थान उपनिवेशन (पौंग बांध विस्थापितों को इ.ग.न.प. क्षेत्र में आंवटन नियम 1975 के नियम 3 के तहत गजट में आरक्षित नहीं हुई थी और ना ही भूमि में पौंग बांध विस्थापितों के लिए भूमि का आरक्षित होने का कोई गजट पेश किया गया है। भूमि आंवटन हुए 43 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है भूमि की समस्त किरतें व बकाया अदा की जा चुकी है तथा भूमि खातेदारी है प्रथम तो चैयरगेन एक निर्वाचित पद है। यह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है। आंवटन 1980 व 1981 का है उस समय सरकारी कर्मचारी को भी आंवटन हो सकता था। इस हेतु नियमों में संशोधन 15.07.1993 को आया। 1980 व 1981 के आंवटन पर लागू नहीं होता। आरबीआई 2002 पेज संख्या 103 प्रमाणशील नहीं है। सुरेन्द्र सिंह का चैयरगेन एवं रमेश कुमार के पास एमबीबीएस डिग्री होने से सरकारी कर्मचारी माना भी नहीं जा सकता।

8. खातेदारी प्राप्त होने भूमि का हस्तांतरण होने से इस अवस्था में आंवटन निरस्त करना न्याय का हनन होगा। स्वयं शिकायतकर्ता ने इसे समझते हुए शिकायत प्रार्थना पत्र दिज्ञा कर लिया है। तहसीलदार द्वारा आवंटित कृषि भूमि पर वर्तमान में बिना भू-रूपांतरण के अकृषि कार्य के होने एवं ऐसा कोई भी तथ्य पक्षकारान के विरुद्ध पेश किया जिससे आवंटित रकबा निरस्त किया जा सके। अप्रार्थीगण के नाम से चक 11 पी में भी कृषि भूमि है। इससे भी यह कृषक पेशा साबित है। तमाम तथ्यों के विचारण से निष्कर्षतः यह पाया गया है कि भूमि विशेष आंवटन के तहत लगभग 43 वर्ष पूर्व आवंटित की गई है, खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। तहसीलदार के वारिसान ईन्तकाल के पश्चात आवंटियों के जायज वारिसों का भूमि पर कब्जा काश्त में है। अतः भूमि का आंवटन विधिसम्मत किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है तथा आवंटियों को किया गया विशेष आंवटन दिनांक 24.09.1980 एवं 06.03.1981 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तरतीव तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 5/9/24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)

R.A.S

अति. जिला कलक्टर

अनूपगढ़